ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

मधुमक्खियों की प्रजातियों का बना पहला नक्शा

रविवारीय, 20 - 26 दिसंबर 2020 वर्ष- दो, अंक-20, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

कृषि मंत्री बादल ने किसानों से की बातचीत

रांची :कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल ने नेपाल हाउस स्थित सभागार में किसानों से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की.

झारखंड के सभी जिले से लगभग 400 किसान टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के साथ जुड़े और उन्होंने कृषि मंत्री सहित एक्सपर्ट के साथ बातचीत की ,उनसे अपने पशुओं के रखरखाव सहित वैक्सीनेशन एवं अन्य चीजों को लेकर बातचीत किया। पशुपालकों ने पशु से संबंधित तो सवाल पूछे ही वहीं अपने खेतों में लगे सब्जी सहित अन्य वस्तुओं के विषय में भी उन्होंने जानकारी मांगी, विभागीय मंत्री बादल सहित कृषि सचिव और निदेशक ने त्वरित गति से अपने अधिकारियों को ग्राउंड पर जाकर किसानों के हर समस्या के समाधान करने का निर्देश भी दियाा।

मंत्री बादल ने कहा कि आने वाले समय में हम कोने कोने के किसानों के साथ इसी तरह लगातार टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और उनके समस्या का समाधान तीव्र गति से हो यह सुनिश्चित करेंगे।

स्पेशल ट्रेनों के समय सारणी में परिवर्तन

रांची : हटिया तथा रांची स्टेशन पर निम्नलिखित ट्रेनों के समय सारणी में परिवर्तन किया गया है।

23/12/2020 से संबलपुर से खुलने वाली ट्रेन संख्या 08311 संबलपुर – मंडुवाडीह स्पेशल ट्रेन का हटिया एवं रांची स्टेशन पर समय सारणी में परिवर्तन किया गया है, हटिया आगमन 19:20 बजे के स्थान पर 19:30 बजे तथा प्रस्थान 19:25 बजे के स्थान पर 19:35 बजे होगा, एवं रांची आगमन 19:40 बजे के स्थान पर 19:50 बजे तथा प्रस्थान 19:55 बजे के स्थान पर 20:05 बजे होगा।

20/12/2020 से ट्रेन संख्या 05027 हटिया – गोरखपुर स्पेशल ट्रेन का राँची स्टेशन पर समय सारणी में परिवर्तन किया गया है , राँची आगमन 17:05 बजे के स्थान पर 17:10 बजे तथा प्रस्थान 17:15 बजे के स्थान पर 17:20 बजे होगा।

हर हाल में रोकें राज्य में अवैध खनन :मुख्यमंत्री

संवाददाता

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध खनन पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। खान एवं भूतत्व विभाग राज्य के विभिन्न अवैध बालू घाटों और पहाड़-चट्टान इत्यादि जगहों पर अवैध पत्थर खनन सहित सभी अवैध माइनिंग पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करे। खान एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग तथा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में कही।

मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर माइंस क्षेत्रों में चलने वाले ट्रकों का पेपर, चालान एवं परमिट जांच अवश्य करें। वैसे ट्रक जो कोयला अथवा अन्य भू-संपदा की चोरी कर ढुलाई करते हुए पकड़े जाते हैं, उन ट्रकों को थाने पर सड़ाएं नहीं बल्कि वैसे मामलों में पेनाल्टी का प्रावधान करें । थानों में अधिक दिनों तक ट्रकें खड़ी न रहें । राज्य के विभिन्न थानों में इस तरह के मामलों में जितने ट्रक पकड़े गए हैं, उनका निष्पादन आगामी मार्च महीने तक अवश्य कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि माइंस क्षेत्रों में चलने वाले ट्रक एक परमिट का बार-बार उपयोग नहीं कर सकें, इस पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना है कि एक चालान पर कई बार ढुलाई की जाती है, इस पर भी रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने माइंस क्षेत्रों में मिनरल चेकपोस्ट बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।

राज्य में अवैध पत्थर खनन पर हर हाल में रोक लगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कितने पहाड़ों अथवा चट्टानों पर अवैध पत्थर खनन किया जा रहा है, इसका डाटा तैयार करें। राज्य में अवैध पत्थर खनन पर हर हाल में लगाम लगे, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को माइनिंग सर्विलांस सर्विस सिस्टम डेवलप करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने नया माइनर मिनिरल पॉलिसी तैयार करने और उस पॉलिसी में एसटी, एससी एवं महिला समूहों को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने वैध खनन से होने वाले राजस्व को बढ़ाने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया।

डीएमएफटी फंड की उपयोगिता रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश

हेमन्त सोरेन ने डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड का उपयोग किस प्रकार माइनिंग क्षेत्रों में किया जा रहा है, इसकी उपयोगिता रिपोर्ट राज्य के विकास आयुक्त को उपलब्ध कराएं। विकास आयुक्त अपने स्तर पर डीएमएफटी फंड की समीक्षा करें। इस निमित्त खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव जिलों के उपायुक्तों को अपनी ओर से निर्देशित करें। खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि के उपयोग का स्टेटस एवं डिटेल राज्य सरकार को उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमएफटी फंड को मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सड़क निर्माण इत्यादि के विकास कार्य पर खर्च किया जाना है। डीएमएफटी फंड का उपयोग पेयजल और स्वच्छता विभाग समन्वय स्थापित कर माइनिंग क्षेत्रों में अवस्थित गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना पर फोकस करे। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्टेट जूलॉजिकल लैबोरेट्री को आधुनिक रूप से क्रियान्वित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में डायमंड माइनिंग एवं गोल्ड माइनिंग ऑक्शन का रास्ता जल्द निकालने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने खान एवं भूतत्व विभाग की रिक्तियों की समीक्षा करते हुए खाली पदों पर रोस्टर क्लीयरेंस कर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव के श्रीनिवास ने पिछले 3 वर्षों का रेवेन्यू टारगेट और कलेक्शन की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण में वृद्धि को लेकर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, केके खंडेलवाल,राजीव अरुण एक्का, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव के श्रीनिवास, खान विभाग के निदेशक शंकर सिन्हा, भूतत्व विभाग के निदेशक विजय कुमार ओझा सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे

अवैध खनन का गढ़ है झारखंड

खनिजों के मामले में झारखंड देश की रीढ है। यूरेनियम, कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, एस्बेस्टर? तकरीबन प्रत्येक खनिज झारखंड की रत्नगर्भा धरती में दबी पड़ी है। यही कारण है कि अवैध खनन का गढ़ भी झारखंड रहा है। खनिजों के अवैध खनन के अलावा झारखंड के पर्यावरण को सबसे बड़ा नुकसान पत्थरों की अवैध कटाई से हो रही है। महज दस सालों में ही राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में कई छोटे बड़े पहाड़ काट डाले गये और वो अब तकरीबन लुप्त हो चुके हैं।

अवैध क्रशर और पत्थरों की कटाई ने उन पहाड़ों को भी नहीं बख्शा जिसकी पूजा की जाती रही है। सरकार के कितने भी रोक और आदेश के बावजूद झारखंड के अंदरूनी इलाकों में बेरोक टोक क्रशर भी चालू हैं और पहाड़ों की कटाई भी।

बच गयी नन्हें हाथी की जान

सिदाम महतो

तमाड़ वन क्षेत्र अंतर्गत जिलिंगसेरेंग और सालगाडीह गांव के समीप हाथी का एक बच्चा कुँए में गिर गया। हाथियों का झुंड शाम ढलते ही जंगल से खेत की ओर निकल जाता है।15 दिसम्बर की रात को भी हाथियों का झुंड जिलिंगसेरेंग जंगल से निकल कर गांव के खेत की ओर निकल गया । झुंड में लगभग 7-8 साल का एक हाथी का बच्चा भी है। खेत मे बने कुंए में हाथी का बच्चा गिर गया। झुंड में शामिल अन्य हाथी , इस नन्हे हाथी को निकालने का प्रयास करते हैं। हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज से ग्रामीणों की नींद खुली और ग्रामीण समझ गए कि हाथियों का झुंड रोज की तरह आज भी खेत मे पहुंचे हैं।पर इस तरह चिंघाड़ने की आवाज रोज नही आती है। आज जरूर कुछ अनहोनी हुई है। जब हाथियों पर आफत आती है , इस तरह चिंघाड़ने की आवाज आती है। हाथियों ने अपने परिवार के नन्हे सदस्य को कुंए से निकलने के लिए सुबह तक मेहनत करते रहे। अंत मे बच्चे को कुँए में छोड़कर पास के जंगल मे चले गए।

सुबह ग्रामीणों की नजर कुंए में गिरे हाथी के बच्चे पर पड़ी। कुंए में हाथी गिरने की खबर आग की तरह फैली। लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। हाथी का बच्चा कुंए में से निकलने की नाकाम कोशिश करता रहा। लोग हाथी के बच्चे की हरकत को मोबाइल में भी कैद करने लगे। इंसान का दिल जानवरों के लिए भी धड़कता है। किसी तरह नन्हे हाथी की जान बच जाए!मौजूद भीड़ में से किसी ने वन विभाग को सूचना दे दी। कुछ घण्टों के बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची कुंए के पास जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू की गई। कुंए की दीवार को तोड़कर नन्हे हाथी को निकालने के लिए रास्ता बनाया जाने लगा। संकट में फंसे हाथी के बच्चे को भी पता चल गया कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। नन्हा हाथी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ देने लगा। दो घण्टे तक चले इस राहत कार्य के बाद, मशीन द्वारा बनाए रास्ते से कुंए से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर नन्हे हाथी ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों के शोर के बीच नन्हा हाथी जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। एक नन्हे हाथी की जान बच गयी।

राज्यपाल ने किया रांची विश्विद्यालय के कुलसचिव डॉ. मुकुन्द चंद्र मेहता की दो पुस्तकों का लोकार्पण

राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16 दिसंबर को राज भवन के दरबार हॉल में राँची विश्विद्यालय के कुलसचिव डॉ. मुकुन्द चंद्र मेहता द्वारा लिखित दो पुस्तकों Human Resource Development एवं Corporate Governance, Ethics and Social Responsibility of Business का लोकार्पण किया । राज्यपाल महोदया ने उन्हें इन पुस्तकों के लेखन कार्य के लिये बधाई दी।

कस्तूरी महिला सभा ने किया गर्म कपड़ों का वितरण

रांची 19 दिसम्बरः कस्तूरी महिला सभा के तत्वावधान में सीएमपीडीआई परिसर में गर्म वस्त्र का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक शेखर सरन एवं कस्तूरी महिला सभा की अध्यक्षा मीता सरन ने गर्म वस्त्र का वितरण किया। इस अवसर पर कस्तूरी महिला सभा की श्रीमती उषा मिश्रा एवं श्रीमती नीरजा गोमास्ता तथा सीएमपीडीआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी सुमित कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक (एचआरडी), महाप्रबंधक (नगर अभियंत्रण, विभागाध्यक्ष (ईपी-सीएम) प्रभात कुमार, गोंदवाना प्राइमरी स्कूल की प्राचार्या श्रीमती ममता सिंह एवं बिरसा उच्च विद्यालय के शिक्षकगण भी उपस्थित थे।

मौके पर शेखर सरन ने कहा कि महिला सभा द्वारा किया गया सामाजिक कार्य एक अच्छा प्रयास है। इसे जारी रखने की आवश्यकता है। इसके लिए महिला सभा बधाई के पात्र हैं। इस प्रयास में सीएमपीडीआई प्रबंधन का सहयोग रहेगा। वंचित एवं जरूरतमंदों के प्रति समाज का कुछ दायित्व बनता है उसे पूरा करना चाहिए।

अपर रेल प्रबंधक ने व्यवसायियों के साथ किया वेबिनार

रांची : अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित की मुख्य उपस्थिति में 18 दिसंबर को वेबिनार के माध्यम से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गयी ।लदान में वृद्धि हेतु तथा अनलोडिंग को सुचारू रूप से करने के लिए अपर मंडल रेल प्रबंधक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन के माध्यम से व्यवसायियों के साथ चर्चा की उनकी समस्याओं को जाना तथा उनके सुझाव भी लिए ।

रेल प्रशासन ने व्यवसायियों को आश्वस्त किया कि उन्हें गुड्स शेड एवं परिसर में और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही व्यवसायियों से अनुरोध किया गया कि रेलवे के प्रति उनके जो भी बकाया राशि है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान कर दे, व्यवसायियों ने विश्वास दिलाया कि बकाए राशि की भुगतान जल्द कर देंगे

व्यवसायिक प्रतिष्ठान की ओर से संतोष कुमार मलिक - बीपीसीएल, रवि भूषण सिंह - हिंडालको लोहरदगा, - गीतांश अग्रवाल - सीसीएल रजरप्पा एवं एचईसी के प्रतिनिधि, विकास प्रताप ने चर्चा में भाग लिया। तथा रेल प्रशासन की ओर से, वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) अमित कंचन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता पंकज कुमार, मंडल वित्त प्रबंधक (समन्वय) टीकाराम मीणा एवं वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों ने चर्चा में भाग लिया।

नया साल आने से कोरोना खत्म नहीं हो जायेगा

मुरलीधर

साल 2020 को सारा विश्व एक मनहुस साल की तरह देख रहा है। मनहुस हो भी क्यों नहीं भारत में ही साल 2020 बहुत सारे कलाकारों, सेलिब्रेटी की मौत के अलावा कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का भी शिकार है।

सचमुच यह साल एक बुरे सपने की तरह बीत रहा है और दुनिया इस भ्रम में है कि नए साल में महामारी का सूरज भी डूब जाएगा। लेकिन सच यह है कि वायरस किसी कैंलेडर को सम्मान की नजर से नहीं देखता। उसे तो बस मेजबान यानी होस्ट चाहिए। दुनिया के 7 बिलियन से अधिक लोग उसकी विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने के लिए पर्याप्त हैं। नोवेल कोरोनावायरस को चीन के एक बाजार में मानव मेजबान को खोजे करीब एक साल हो गया है। तब से लेकर अब तक यह करीब 200 देशों में फैलकर 16 लाख से अधिक लोगों की जान ले चुका है। बहुत से देश महामारी के प्रारंभिक चरण के मुकाबले उच्च संक्रमण दर से जूझ रहे हैं। बहुत से देशों का दावा है कि उन्होंने वक्र को समतल कर दिया है और अब दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुनिया महामारी के प्रभाव से दरक सी गई है। एक साल बाद महामारी को बारीकी से देखने की जरूरत है जो सौ साल में एक बार स्वास्थ्य पर गंभीर संकट खड़ा करती है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वायरस आगे भी अपना काम करता रहेगा यानी मेजबान खोजता रहेगा। बहरहाल महामारी के एक साल होने के क्या मायने हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले यह जानना जरूरी है कि वायरस दुनिया में स्थायी कैसे बन रहा है। अलग-अलग समूह के लिए इसके अलग-अलग मतलब हैं। यह स्वास्थ्य पर संकट तो बना रहेगा लेकिन इसका सबसे गंभीर प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय हैं।

महामारी हमें इस तथ्य की रह रहकर याद दिलाती रहेगी कि हम राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से दरकिनार कर किए जाने को अभिशप्त हैं। हम भले ही एक ग्रह पर रह रहे हों लेकिन ''एक दुनिया'' में नहीं हैं। हमारी शासन व्यवस्था और विकास को परिभाषित करने वाली असमानता तब खुलकर सामने आ जाती है जब हम इस महामारी से लड़ते हैं। देशों के बीच ही नहीं बल्कि देश और समाज के भीतर की असमानता भी

महामारी सामने ले आई है। आंकड़े बताते हैं कि गरीब आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे वह गरीब देश की हो या अमीर। देश के भीतर विकास में क्षेत्रीय असमानता ने जनसंख्या के कुछ समूहों को अधिक प्रभावित किया है।

महामारी के दौर में असमानता गरीबों और वंचितों को आर्थिक रूप से तोड़ देती है। उदाहरण के लिए भारत में असंगठित क्षेत्र को सबसे अधिक आर्थिक क्षति पहुंची और इसी वर्ग की नौकरियां सबसे ज्यादा गईं। देशों की बात करें तो सबसे कम विकसित देशों को भीषण आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, इसलिए ये देश कल्याण कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च में कटौती कर रहे हैं। विकसित देशों में भी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समझा जाने वाला तबका ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यानी इसी तबके को जानमाल की सबसे अधिक क्षति पहुंची है। ऐसी स्थिति में दुनिया सतत विकास लक्ष्यों से बुरी तरह पिछड़ जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गरीब और गरीब हो रहा है। हालांकि अमीर व्यक्ति अपनी दौलत के बूते महामारी के संकट से आसानी से पार कर लेगा।

पर्यावरण की नजर से देखें तो जब देशों ने सख्त लॉकडाउन लागू किया तो हमने नीले आसमान और साफ हवा'' का जश्न मनाया। इसने एक बार फिर याद दिलाया कि हमने अपने पर्यावरण के साथ कितना बुरा सलूक किया है। अब एक साल बाद पता चल रहा है कि यह हमारी समृद्धि और उपभोग की अस्थायी झलक भर थी जिसने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी से हमें विमुख कर दिया है। ऐसा तब है जब हमारी अर्थव्यवस्था प्रकृति पर आधारित है। कार्बन का उत्सर्जन कम जरूर हुआ है लेकिन इतना नहीं कि वैश्विक तापमान कम किया जा सके। यह साल तीन सबसे गर्म सालों में शामिल हो गया है। इससे स्पष्ट है कि दुनिया उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के ठीक रास्ते पर नहीं है।

महामारी में गुजरे साल ने हमें बता दिया है कि हमने धरती और जीवों को कितना नुकसान पहुंचाया है। इसके गुनहगार हम ही हैं। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि महामारी ने धरती से हमारे संबंधों को पुन: परिभाषित किया है। जो भी हो लोगों को इस भ्रम में तो कतई नहीं रहना चाहिये कि साल 2020 खत्म होते ही कोरोना भी खत्म हो जायेगा।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

सबसे बेहतर हो सकता है झारखंड

हाल के दिनों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, जलाशयों की साफ सफाई को लेकर गंभीरता दिखाई है और इनके संरक्षण को लेकर आदेश भी दिये हैं। अवैध खनन को हर हाल में रोकने का आदेश भी दिया है। ये एक अच्छी खबर है कि झारखंड में सरकार वन पर्यावरण को बचाने को लेकर संजीदगी दिखा रही है और इसके लिये कई योजनाओं को प्रारंभ करने की घोषणायें भी की गयी हैं। इको टूरिज्म से लेकर, झारखंड के जिलों में वृक्षारोपण, जलसंचयन की कई योजनाओं का खाका खींचा गया है जो झारखंड के लिये संजीवनी का काम करेंगे, बशर्ते ये सभी योजनायें धरातल पर अच्छे से उतर जायें।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेतरहाट घूमने गये थे और वहां के आवासीय विद्यालय को देखने के बाद उनका बयान था कि बचपन से इस स्कूल को देखने की इच्छा थी जो अब पूरी हुयी। इस दौरे पर मुख्यमंत्री ने नेतरहाट के खूबसूरती को देखा और अभिभूत हुये। शायद इसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री झारखंड में इको टूरिज्म को बढावा देने से लेकर, अवैध खनन को रोकने, फलदार वृक्षों को लगाने पर्यावरण बचाने की योजनाओं को ला रहे हैं। यह राज्य के लिये अच्छा शगुन है।

वैसे भी झारखंड में कृषि, बागवानी, हॉर्टीकल्चर के रोजगार के साथ ही यहां की असीम खूबसूरती को इको टूरिज्म में बढ़लने की अपार संभावना है। इस पर कार्य किया जाये तो झारखंड प्रदूषणरहित आजीविका में सबसे बेहतर करेगा।

अगर हम प्राकृतिक संसाधनों के नजरिये से देखें तो झारखडं विश्व के कुछ सबसे समृद्ध इलाकों में से एक है। दुनिया की तकरीबन प्रत्येक खनिज यहां उपलब्ध है, पर उसकी प्राप्ति के लिये अवैध खनन भी यहां की संस्कृति में शामिल है। चाहे वह बालू का अवैध खनन हो या क्रशर उद्योग के लिये पहाड़ों और चट्टानों की अवैध कटाई।अफसोस की राज्य में खनिजों के लूट के लिये वैध अवैध सारे तौर तरीके लंबे समय से जारी हैं, पर इसका लाभ स्वयं झारखंड को नहीं मिला।

वर्तमान मुख्यमंत्री के फलदार वृक्षों को लगाने से लेकर, वन संरक्षण के लिये जंगलों की जियोमैपिंग, नदियों के किनारे वृक्षारोपण का आदेश सराहनीय है पर इसकी सफलता के मुख्यमंत्री को स्वयं मोनिटरिंग करनी होगी। ताकि इसके नाम पर उल्टे पर्यावरण की बर्बादी न हो। आखिर पिछली सरकार में भी सौंदर्यीकरण का अभियान बहुत ही जोर शोर से चला था और हश्र रांची के जलाशयों की बर्बादी के रूप में सामने नजर आया।

पहाड़ों में लोगों का जीवन हुआ गरीबी का शिकार

साल 2000 में विकासशील देशों के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले 24.3 करोड़ लोग भुखमरी का सामना कर रहे थे वो, संख्या 2017 में बढ़कर 35 करोड़ पर पहुंच गई है। जलवायु में आ रहे बदलावों और जैव विविधता के घटने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में खाने की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। यह जानकारी हाल ही में एफएओ द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट 'वल्नेरेबिलिटी ऑफ माउंटेन पीपल टू फूड इन्सेक्युरिटी' में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि दुनिया की ज्यादातर सबसे महत्वपूर्ण फसलें और मवेशियों की प्रजातियां इन पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को हो रहे नुकसान के चलते पहाड़ों और उन पर निर्भर लोगों पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

विकासशील देशों में स्थिति कुछ ज्यादा ही ख़राब है, यहां खाद्य सुरक्षा की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। जहां वर्ष 2000 में इन इलाकों में रहने वाले 24.3 करोड़ लोग भुखमरी का सामना कर रहे थे, वो संख्या 2017 में बढ़कर 35 करोड़ पर पहुंच गई है। 2017 में जारी आंकड़ों के अनुसार पहाड़ करीब 110 करोड़ लोगों का घर है, जोकि वैश्विक आबादी का 15 फीसदी हैं। इसमें से 100 करोड़ (91 फीसदी) विकासशील देशों में रहते हैं। दुनिया के करीब 27 फीसदी भूभाग पर पहाड़ हैं, जोकि 3.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इनका 54 फीसदी हिस्सा विकासशील देशों में है। यह पहाड़ हमारी भोजन, पानी और ऊर्जा जैसी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह कितने जरुरी हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का 60 से 80 फीसदी मीठा पानी इन्हीं पहाड़ों से मिलता है, जोकि हमारे जीवन का आधार है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फसलें और मवेशी भी इन्हीं पहाड़ों पर मिलते हैं। जो भोजन और दवा सम्बन्धी जरुरत को पूरा करते हैं। इसके बावजूद इनपर इंसानी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और भूमि उपयोग में होते बदलाव का खामियाजा इन पहाड़ों और वहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि इन पहाड़ों का बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम आज दबाव का सामना कर रहा है। ऊपर से यहां के संसाधनों का जिस तरह से दोहन हो रहा है उसके चलते आज यहां रहने वाले लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उनपर भुखमरी और रोजगार के छिनने का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

बीते 20 सालों में वायु प्रदूषण ने दोगुने किये श्वसन रोगी

हाल ही में आये एक कोर्ट के एक फैसले में दुनिया को पहला ऐसा मामला पता चला जिसमें किसी की मौत का ज़िम्मेदार वायु प्रदूषण था। बात हो रही है नौ साल की एला की, जिसकी मौत के नौ साल बाद लंदन के एक कोर्ट ने वायु प्रदूषण को उसकी मौत का कारण माना। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें अब दो राय नहीं कि प्रदूषण जानलेवा है। और ऐसा नहीं कि समस्या बस वहीँ लंदन की है।

ताज़ा शोध बताते हैं कि भले ही क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीसेस (सीओपीडी) और ब्रोन्कियल अस्थमा भारत में आम बीमारियाँ हैं, लेकिन 1990 के दशक से लेकर अगले 20 साल के दौरान भारत में जीडीपी पर बीमारी के बोझ में सीओपीडी का असर दोगुना हो गया है। तेजी से हो रहे इस बदलाव का मुख्य कारण वातावरणीय तथा आंतरिक वायु प्रदूषण हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल में दावा किया था कि वर्ष 2019 के मुकाबले इस साल नवम्बर में दिल्ली की हवा ज्यादा खराब थी। इन कारकों और सांस सम्बन्धी महामारी का संयुक्त रूप से तकाजा है कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये फौरन नीतिगत ध्यान दिया जाए। क्लाइमेट ट्रेंड्स ने सीओपीडी और उसके नीतिगत प्रभावों पर किये गये एक ताजा शोध पर चर्चा के लिये शनिवार को एक वेबिनार आयोजित किया। यह शोध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नेशनल एनवॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) और दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरणीय विज्ञान विभाग के परस्पर सहयोग से किया गया है।

वेबिनार में नीरी के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के वैज्ञानिक और आईसीएमआर के डीडीजी डॉक्टर वी पी सिंह, आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज में प्रोफेसर डॉक्टर सागनिक डे और हिन्दुस्तान टाइम्स की पर्यावरण पत्रकार सुश्री जयश्री नंदी ने हिस्सा लिया। वेबिनार का संचालन क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक सुश्री आरती खोसला ने किया। वेबिनार में दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर-प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा ने इस शोध का प्रस्तुतिकरण किया। इस शोध का उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) पर सीओपीडी के बोझ का आकलन करना, सीओपीडी के स्थानिक महामारी विज्ञान को समझना, दिल्ली के एनसीटी में सीओपीडी के जोखिम वाले कारकों का आकलन करना और दिल्ली के निवासियों के बीच वायु प्रदूषण के लिहाज से व्यक्तिगत जोखिम का अंदाजा लगाना है।

डॉक्टर शर्मा ने शोध की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीसेस (सीओपीडी) और ब्रोन्कियल अस्थमा सांस से जुड़ी सबसे आम बीमारियां हैं। वर्ष 2015 में सीओपीडी ने सीओपीडी की वजह से 104.7 मिलियन पुरुष और 69.7 मिलियन महिलाएं प्रभावित हुईं। वहीं, वर्ष 1990 से 2015 तक सीओपीडी के फैलाव में भी 44.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में सीओपीडी की वजह से पूरी दुनिया में 32 लाख लोगों की मौत हुई, और यह मौतों का तीसरा सबसे सामान्य कारण रहा।

भारत में इसके आर्थिक प्रभावों पर गौर करें तो वर्ष 1990 में 28.1 मिलियन मामले थे जो 2016 में 55.3 दर्ज किये गये। ग्लोबल बर्डेन ऑफ डिसीसेस के अनुमान के मुताबिक वर्ष 1995 में भारत में जहां सीओपीडी की वजह से 5394 मिलियन डॉलर का भार पड़ा। वहीं, वर्ष 2015 में यह लगभग दोगुना होकर 10664 मिलियन डॉलर हो गया।

पिछले कुछ अर्से में वायु प्रदूषण सबसे उल्लेखनीय जोखिम कारक के तौर पर उभरा है। वायु प्रदूषण सीओपीडी के तीव्र प्रसार के लिये जिम्मेदार है। सीओपीडी का जोखिम पैदा करने वाले कारकों में धूम्रपान को सबसे आम कारक माना गया है। तीन अरब लोग बायोमास ईंधन जलाने से निकलने वाले धुएं के जबकि 1.01 अरब लोग तम्बाकू के धुएं के सम्पर्क में आते हैं। इसके अलावा वातावरणीय वायु प्रदूषण, घरों के अंदर वायु प्रदूषण, फसलों की धूल, खदान से निकलने वाली धूल और सांस सम्बन्धी गम्भीर संक्रमण भी सीओपीडी के प्रमुख जोखिम कारक हैं।

इस बात पर गौर करना होगा कि भारत में जनसंख्या आधारित अध्ययनों की संख्या बहुत कम है और पिछले 10 वर्षों के दौरान ऐसा एक भी अध्ययन सामने नहीं आया। दिल्ली एनसीटी के लिये जनसंख्या आधारित एक भी अध्ययन नहीं किया गया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सीओपीडी का सीधा सम्बन्ध वायु प्रदूषण से है। सीओपीडी के 68 प्रतिशत मरीजों के मुताबिक वे ऐसे स्थलों पर काम करते हैं जहां वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। इसके अलावा 45 प्रतिशत मरीज ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां वायु प्रदूषण का स्तर 'खतरनाक' की श्रेणी में आता है। इसके अलावा 70 प्रतिशत मरीजों ने बताया कि वे धूल की अधिकता वाले इलाकों में काम करते हैं।

64 प्रतिशत मरीजों ने बताया कि वे धूम्रपान नहीं करते, जबकि धूम्रपान करने वाले मरीजों का प्रतिशत केवल 17.5 है। इससे जाहिर होता है कि लोगों पर अप्रत्यक्ष धूम्रपान का असर कहीं ज्यादा हो रहा है।

नीरी के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार ने वेबिनार में अपने विचार रखते हुए कहा कि यह अध्ययन भारत के नीति नियंताओं के लिये नये पैमाने तैयार करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि जब हम विभिन्न लोगों से डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं तो यह बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास अनेक स्रोत है जो अन्य देशों से अलग हैं। दिल्ली को लेकर किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि यहां केरोसीन से लेकर कूड़े और गोबर के उपलों तक छह-सात तरीके के ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिनसे निकलने वाला प्रदूषण भी अलग-अलग होता है। आमतौर पर बाहरी इलाकों में फैलने वाले प्रदूषण की चिंता की जाती है लेकिन हमें चिंता इस बात की करनी चाहिये कि आउटडोर के साथ इंडोर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती में भी हैवी मेटल्स होते हैं। डॉक्टर शर्मा के अध्ययन में दिये गये आंकड़े खतरनाक रूप से बढ़े नहीं हैं, लेकिन वे सवाल तो खड़े ही करते हैं। दिल्ली में 15-20 साल पहले डीजल बसों और वैन में सीएनजी से संचालन की व्यवस्था की गयी। बाद में पता चला कि सीएनजी से बेंजीन गैस का उत्सर्जन होता है। इस दौरान प्रदूषण के स्तर बहुत तेजी से बढ़े हैं। यह और भी चिंताजनक है कि छोटे छोटे शहरों में भी प्रदूषण के इंडेक्स दिल्ली से मिलते-जुलते हैं।

सागनिक डे- यह अध्ययन हमें बताता है कि हम प्रदूषण के सम्पर्क के आकलन में पैराडाइम शिफ्ट के दौर से गुजर रहे हैं। हमें सिर्फ एक्सपोजर असेसमेंट करने मात्र के पुराने चलन से निकलना होगा। ऐसी अन्य स्टडीज से चीजें और बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि आज हमें हाइब्रिड मॉनीटरिंग अप्रोच की जरूरत है। कोई व्यक्ति जो आईटी सेक्टर में काम करता है, जाहिर है कि वह बंद जगह पर ही काम करता होगा। अंदर प्रदूषण का क्या स्तर है उसे नापना बहुत मुश्किल है। हमें 24 घंटे एक्सपोजर के एकीकृत आकलन का तरीका ढूंढना होगा। हमारे पास अंदरूनी प्रदूषण को नापने के साधन बेहद सीमित संख्या में हैं।

अध्ययन के मुताबिक 30 मिनट के सफर से एक्सपोजर का खतरा होता है। वायु प्रदूषण का मुद्दा सिर्फ इसलिये गम्भीरता से लिया गया क्योंकि इसने सेहत के लिये चुनौती खड़ी की। अभी तक किये गये अध्ययनों में ज्यादातर डेटा वह है जो कहीं और से लिया गया है, मगर किसी स्थान के मुद्दे अलग होते हैं। उनमें कुपोषण भी शामिल है। वायु प्रदूषण सांस सम्बन्धी बीमारियों के साथ-साथ दिल की बीमारियां, मानसिक रोग और समय से पहले ही जन्म समेत तमाम चुनौतियां पेश करता है।

क्लाइमेट कहानी से साभार

पेरिस समझौते के लक्ष्य मानवता के सबसे महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य लक्ष्य भी हैं

भले ही COP26 UN जलवायु वार्ता में फ़िलहाल साल भर का समय हो, लेकिन दुनिया भर के डॉक्टरों और तमाम स्वास्थ्यकर्मियों को अभी से ही एकजुट हो जाना चाहिए उस वार्ता को सार्थक बनाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों का पूरा होना सीधे तौर पर पूरी मानवता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकता है।

इस विचार को विस्तार से द जर्नल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ में एक लेख में उल्लेखित किया गया है। लेख में स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों से पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी भूमिका निभाने के लिए आग्रह किया गया है। लेख के अनुसार नवंबर 2021 में होने वाले COP 26 के परिणाम को प्रभावित करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों और उनके संगठनों को अभी से एकजुट होना होगा।

हेल्थ प्रोफेशनल्स, द पेरिस अग्रीमेंट, एंड द फीयर्स अर्जेंसी ऑफ़ नाउ शीर्षक के इस लेख को पेरिस समझौते की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ एलायंस के निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा लिखा गया है। इस लेख के अनुसार, ''स्वास्थ्य पेशेवरों को पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे विज्ञान-आधारित अधिवक्ताओं के बढ़ते वैश्विक समुदाय में शामिल होना चाहिए। सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने से अभिनेताओं के विविध और व्यापक गठबंधन की आवश्यकता होती है। हमें विश्व की ऊर्जा, परिवहन, कृषि और अन्य भूमि उपयोग प्रणालियों को बदलने के लिए समर्थन और निर्माण करना चाहिए, जो मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर्याप्त है और जलवायु प्रणाली की मरम्मत करता है जिस पर यह निर्भर करता है। स्वास्थ्य पेशेवरों के रूप में, हमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक और राजनीतिक निर्माण करने में मदद करनी चाहिए, जिस तरह हम नशे की लत को समाप्त करने और वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारी को रोकने के लिए काम करते हैं। GCHA बोर्ड के सदस्य और जलवायु और चिकित्सा पर मेडिकल कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवर्ड मेबाच, ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, "हमारा मानना है कि पेरिस समझौते के लक्ष्य मानवता के सबसे महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य के लक्ष्य भी हैं।'' वो आगे कहते हैं, "फ़िलहाल एक-एक दिन की देरी भारी पड़ रही है और तमाम बाधाओं का भी सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन यह अवसर है हम स्वास्थ्य पेशेवरों के के लिए एकजुट होने का। आगे, GCHA के कार्यकारी निदेशक जेनी मिलर कहते हैं, "उडढ26 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आने की संभावना है, जो दुनिया भर में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मानव स्वास्थ्य, समृद्धि, इक्विटी और न्याय के भाग्य को निर्धारित कर सकता है। और इसमें स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।'' इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए लिआसन अधिकारी, ओमानिया एल ओमरानी ने कहा, "दुनिया भर में, हजारों अस्पताल और स्वास्थ्य प्रणाली पहले से ही जलवायु पर काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक वैश्विक आंदोलन का गठन, लचीलापन और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच - और यह राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है"।

द क्लाइमेट एंड हेल्थ एलायंस में एसोसिएट प्रोफेसर यिंग झांग, कहते हैं ''तूफ़ान और बाढ़ जैसी चरम मौसम घटनाएँ सीधे तौर पर लोगों पर असर करते हैं और हम वैसे ही वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित बीमारियों, दूषित भोजन और पानी से बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देख रहे हैं। जो लोग हाशिए पर हैं और बेरोजगार हैं, उन्हें आमतौर पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी पर पड़ेगा।''

जलवायु से जुड़ी आपदाओं के चलते 2050 तक अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे 4.5 करोड़ भारतीय

2050 तक भारत के 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग जलवायु से जुड़ी आपदाओं के चलते अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे यह आंकड़ा वर्तमान से करीब 3 गुना ज्यादा है

जलवायु संकट एक ऐसा खतरा है जिसे और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी कीमत आज सारी दुनिया भुगत रही है। भारत जैसे देशों में जहां आज भी बड़ी आबादी गरीबी और भुखमरी का शिकार है। वहां यह समस्या और गंभीर रूप लेती जा रही है। इसी समस्या का एक पहलु एक्शन ऐड द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट 'कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट इनएक्शन' में सामने आया है। इसके अनुसार 2050 तक भारत के 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग जलवायु से जुड़ी आपदाओं के चलते अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह आंकड़ा वर्तमान से करीब 3 गुना ज्यादा है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सूखा, समुदी जलस्तर के बढ़ने, जल संकट, कृषि और इकोसिस्टम को हो रहे नुकसान जैसी आपदाओं के चलते देश में 1.4 करोड़ लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि इन आंकड़ों में बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं से होने वाले प्रवास को नहीं जोड़ा गया है, वर्ना यह आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा होता, क्योंकि यह देश बड़े पैमाने पर बाढ़ और तूफान जैसी अचानक आने वाली त्रासदियों का दंश झेल रहे हैं।

अर्थव्यवस्था को होगा 7 से 13 फीसदी का नुकसान

विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नेपाल के 65 फीसदी, भारत के 41 फीसदी, बांग्लादेश के 38 फीसदी, पाकिस्तान के 36 फीसदी और श्रीलंका के 24 फीसदी श्रमिक कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। इन देशों में खेती काफी हद तक जलवायु पर निर्भर है। ऐसे में यदि सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है तो उसका खामियाजा सबसे ज्यादा कृषि को ही उठाना पड़ता है। भारत के 60 फीसदी खेतों की सिंचाई बारिश पर निर्भर हैं, ऐसे में यदि कृषि को नुकसान होता है तो उसका बोझ पहले से ही गरीबी में जी रहे किसानों पर बहुत ज्यादा पड़ता है।

इस वर्ष मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट द्वारा किए एक शोध से पता चला है कि यदि जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम न उठाए गये तो 2050 तक दक्षिण एशियाई देश अपने जीडीपी का 2 फीसदी खो देंगे। जो सदी के अंत तक बढ़कर 9 फीसदी हो जाएगा।

जलवायु परिवर्तन से डॉल्फिन की त्वचा के बड़े हिस्से में हुआ रोग

एजेंसियां

अध्ययन में पहली बार ताजे पानी वाली बॉटलनोज़ डॉल्फ़िन की त्वचा की बीमारी के बारे में विस्तार से बताया गया है

दुनिया के सबसे बड़े समुद्री स्तनधारी केंद्र के वैज्ञानिकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने डॉल्फ़िन में एक नए त्वचा रोग की पहचान की है, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। यह बीमारी 2005 में पहली बार सामने आई थी। अब पहली बार वैज्ञानिक दुनिया भर के तटीय डॉल्फिनों को प्रभावित करने वाली स्थिति के कारणों का पता लगाने में सफल हुए हैं। जलवायु परिवर्तन द्वारा पानी के खारेपन में कमी के कारण, डॉल्फ़िन अपने शरीर के चारों ओर चकतीदार और उभरी हुए त्वचा, एक तरह के घावों को विकसित करती हैं। ये घाव कभी-कभी उनकी त्वचा के 70 प्रतिशत हिस्से तक फैल जाते हैं।

इस अध्ययन में पहली बार ताजे पानी वाली बॉटलनोज़ डॉल्फ़िन की त्वचा की बीमारी के बारे में विस्तार से बताया गया है। अध्ययन हाल के वर्षों में लुइसियाना, मिसिसिपी, अलबामा, फ्लोरिडा और टेक्सास और ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण हिस्सों में किया गया। इन सभी स्थानों में पानी के खारेपन में अचानक आई भारी कमी को एक सामान्य कारण माना गया था।

तटीय डॉल्फ़िन अपने समुद्री आवास में खारेपन के स्तर में आने वाले मौसमी बदलाव के आदी होते हैं, लेकिन वे मीठे पानी में नहीं रहते हैं। लगातार बढ़ते तूफान और चक्रवात जैसे तूफान की घटनाओं के खतरे, खासकर यदि वे सूखे की स्थिति से पहले होते हैं, बारिश की अधिक मात्रा को जमा कर लेते हैं जो तटीय जल को मीठे पानी में बदल देते हैं। मीठे पानी की स्थिति महीनों तक बनी रह सकती है, विशेष रूप से तीव्र तूफान जैसे कि हार्वे और कैटरीना के आने के बाद। बढ़ते जलवायु तापमान के साथ, जलवायु वैज्ञानिकों ने अत्यधिक तूफानों का पूर्वानुमान लगाया है, जैसे कि तूफान अधिक बार आएंगे और परिणामस्वरूप डॉल्फ़िन में और अधिक गंभीर बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। ड्यूगन ने कहा विनाशकारी त्वचा रोग तूफान कैटरीना के

बाद से डॉल्फ़िन की मोत का कारण बन रहा है, हम अंत में समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेक्सिको की खाड़ी में इस साल रिकॉर्ड तूफान के मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में अधिक तीव्र तूफान आए। हमें इस तरह के डॉल्फिन को मारने वाले विनाशकारी प्रकोपों के अधिक दिखाई देने की आशंका है। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है।अध्ययन में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के प्रकोप दिखाई दिए हैं, जो दक्षिण-पूर्व ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ और खतरे में आए बुररुन डॉल्फिन को प्रभावित कर रहा है। प्रभावित जानवरों की जांच और उपचार के लिए आवश्यक जानकारी पेशेवरों को दी जा सकती है। वर्तमान में त्वचा रोग से प्रभावित डॉल्फ़िन लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

2005 में आए तूफान कैटरीना के बाद न्यू ऑरलियन्स के पास लगभग 40 बॉटलनोज़ डॉल्फ़िन पर शोधकर्ताओं ने घातक त्वचा रोग को पहली बार देखा था। ड्यूगिनन ने कहा चूंकि समुद्र के तापमान में गर्माहट से दुनिया भर के समुद्री स्तनधारियों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस अध्ययन के निष्कर्ष तटीय क्षेत्रों में रहने वाली डॉल्फिनों की बीमारी के प्रकोप को बेहतर ढ़ग से समझने में मदद करेगा। जिनका पहले से ही रहने की जगहों का नुकसान और उनमें आ रही कमी से ये खतरे में हैं। हम आशा करते हैं कि यह घातक बीमारी को कम करने के लिए पहला कदम होगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महासागर में रहने वाले जीव इसका मुकाबला करेंगे।

हनीफ्रॉड खुलासे का असरः मधुमक्खी पालकों को मिल रही शहद की दोगुनी कीमत

सीएसई ने हाल ही में देश के 10 बड़े ब्रांड द्वारा शहद में चीनी की मिलावट का खुलासा किया है

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की ओर से बड़ी कंपनियों के शहद मिलावट कारोबार का भंडाफोड़ होने के बाद मधुमक्खी पालक किसानों को बड़ी राहत मिली है। करीब पांच बरस बाद देशभर में सरसों वाली शहद (मस्टर्ड लिक्विड शहद) के दाम में दोगुनी बढ़त हुई है। इससे पहले किसानों को अपने कच्चे शहद की लागत तक निकालने में परेशानी हो रही थी। कोरोनाकाल में जब शहद की मांग चरम पर पहुंची तबभी मधुमक्खीपालकों को कंपनियों को कच्ची शहद 60 रुपये किलो तक बेचनी पड़ी।

राजस्थान के अलवर जिले में करीब 10 हजार किसानों के समूह ऑल इंडियन बी-कीपर्स फेडरेशन के अध्यक्ष नबाब सिंह ने कहा कि वे मधुमक्खी पालकों की तरफ से वे सीएसई की इस मुहीम का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि मिलावट कारोबार का खुलासा होने के बाद से बीते पांच बरस में पहली बार ऐसा है जब उन्हें कच्चे शहद का प्रति किलो दाम 130 रुपये तक मिल रहा है। जबकि मई, 2020 महीने में प्रति किलो कच्चे शहद का दाम उन्हें महज 60 रुपये ही मिल रहे थे। इस दोगुनी बढोत्तरी की वजह से किसान खुश हैं।

वर्ष 2015 में स्थापित इंडियन बी-कीपर्स एसोसिएशन ने बताया कि वे अब भी मधुमक्खी पालक से लेकर ऊंचे दर्जे तक कड़ी निगरानी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। संगठन के नवाब सिंह ने कहा कि ब्रांडेड कंपनियों को शहद मुहैया कराने वाली पंजाब-हरियाणा और राजस्थान व उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मदर कंपनियां मधुमक्खी पालकों से रॉ शहद किस दाम में खरीदती हैं, इसका हिसाब और निगरानी रखी जानी चाहिए। क्योंकि किसानों से मदर हनी कंपनियां बेहद कम दाम में कच्चा शहद बीते कई वर्षों से खरीद रही हैं और फिर मिलावटी कारोबार का नेक्सस काम करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा : वन, पर्यावरण संरक्षण के लिये विस्तृत कार्य योजना बनायें

संवाददाता

वन संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत, पेड़ों के कटाव को रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाए जाए

हरमू नदी तथा स्वर्णरेखा नदी के तटीय इलाकों में वृहत पैमाने पर पर वृक्षारोपण करने का निर्देश

वनों की जियो मैपिंग कराई जायेगी हर प्रखंड में एक नर्सरी विकसित करने की पहल होगी

रांची : हेमन्त सोरेन ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा की, पर्यावरण संरक्षण के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया और कहा कि राजधानी रांची और उसके आसपास की पहाड़ियों का अतिक्रमण रोकने और हरियालीकरण तथा हरमू नदी तथा स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल से लेकर उसके तटीय इलाकों में वृहत पैमाने पर पर वृक्षारोपण करने की दिशा में कार्य योजना बनाई जाए । मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया । मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों खासकर राजधानी रांची में मध्यम आकार के पौधों को लगाने की दिशा में कदम उठाने को कहा । इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने वनों के संरक्षण और जंगलों के कटाव को रोकने समय अन्य क्षेत्रों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया ।

वन रोपण को बढ़ावा मिले

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों के विस्तार के लिए जंगल के साथ गैर वन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएं । जहां ओपन जंगल है उसे मॉडरेट जंगल और मॉडरेट वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए । देवघर, पाकुड़, दुमका और धनबाद जैसे जिलों में सघन वन क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में विभाग पहल करें ।

नर्सरी की संख्या बढ़ाई जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नर्सरी की संख्या बढ़ाने की दिशा में विभाग काम करें ।वर्तमान में वन विभाग द्वारा 108 नर्सरियों का संचालन किया जा रहा है ।मुख्यमंत्री ने हर प्रखंड में एक नर्सरी विकसित करने को कहा । यह नर्सरी कम से कम 5 एकड़ जमीन में हो ।इन नर्सरियों मैं वैसे पौधों की व्यवस्था हो , जो किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है । इस मौके पर विभाग द्वारा बताया गया कि उनकी नर्सरियों में 5 रुपए में विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे उपलब्ध है ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को यह जानकारी मिले इसके लिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोग यहां अपनी जरूरत के हिसाब से पेड़ और पौधे लेने के लिए आ सके ।

वनोपज को भी बढ़ावा देने की पहल हो

यहां जनजातीय आबादी आज भी वनोपज के जरिए जीविकोपार्जन करती है ।अतः वनोपज को बढ़ावा देने की दिशा में भी विभाग पहल करे। इसके तहत बैर ,कुसुम ,पलाश जैसे पेड़ लगाए जाएं इससे लाह उत्पादन को बढ़ावा में मदद मिलेगी ।उन्होंने इसकी जिम्मेवारी महिला समूह को देने को कहा ।

सड़कों के किनारे छायादार और फलदार पेड़ लगाए जाएं

मुख्यमंत्री ने सड़कों के किनारे छायादार और फलदार पेड़ लगाने पर भी विशेष जोर दिया । उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे कौन से पेड़ लगाना ज्यादा उपयोगी है , इसकी सूची तैयार की जाए ।

उन्होंने कहा कि आज वन क्षेत्रों का अतिक्रमण तेजी से हो रहा है । ऐसे में वन क्षेत्र की जियो मैपिंग कराकर उसका सीमांकन के साथ घेराबंदी की जाए।

पर्यटन के क्षेत्र में भी विभाग कार्य योजना बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के वन क्षेत्रों में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं । ऐसे में विभाग संभावना वाले वन क्षेत्रों को पर्यटन के लिए विकसित करने की दिशा में ब्लू प्रिंट तैयार करे ।उन्होंने कहा कि पर्यटन संभावित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को गाइड के रूप में रखे ।रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा ।

इन योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया है

- दामोदर,स्वर्णरेखा, गरगा , जुमार और कोनार समेत 11 नदियों के उद्गम स्थल से लेकर उसके तटीय इलाकों बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना तैयार की गई है ।इससे नदियों में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ मिट्टी में कटाव को रोका जा सकेगा ।
- राज्य के सभी प्रमंडल में बायोडायवर्सिटी पार्क निर्माण की योजना बनाई गई है । रांची के आसपास के पहाड़ियों का हरियालीकरण किया जाएगा ।
- राज्य वन्य प्राणी आश्रयणी और नेशनल पार्क के चारों ओर 9 इको सेंसेटिव जोन बनाने की योजना भी तैयार की गई है ।
- स्कूल नर्सरी योजना के तहत हर जिले के एक या दो स्कूलों में 1000 पौधे हर वर्ष लगाने की योजना भी तैयार की गई है ।
- राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.82 प्रतिशत वन है ।अलग राज्य बनने के बाद 1625 वर्ग किलोमीटर में वनों का विस्तार हुआ है ।
- वन क्षेत्र के अंतर्गत 81.42 प्रतिशत प्रोटेक्टेड फारेस्ट और 18. 58 प्रतिशत में रिज़र्व फारेस्ट है ।
- वन विभाग द्वारा वर्ष 2020 -21 में 106 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है ।
- वर्ष 2020 -21 में 204 लाख पौधे लगाए जाने की दिशा में पहल की जा रही है ।
- मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत निजी जमीन पर 75% अनुदान पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं । इस वित्त वर्ष अब तक एक हजार एकड़ जमीन में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं ।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री ए पी सिंह, पी सी सी एफ पीके वर्मा, पीसीसीएफ एके रस्तोगी, एपीसीसीएफ डीके तेवतिया,एपीसीसीएफ एस श्रीवास्तव, एपीसीसीएफ एनके सिंह और विशेष सचिव श्रीमती शैलजा सिंह उपस्थित थीं।

सांसद परिमल नाथवानी ने दिया IIM रांची को सभागार का उपहार

संवाददाता

रांचीः 14 दिसम्बर 2020 भारतीय प्रबंध संस्थान रांची को अपना पहला भवन मिला, जिसका उद्घाटन परिमल नाथवानी, ने किया। कार्यक्रम के अगले दिन यानी की 15 दिसंबर 2020 को, भारतीय प्रबंध संस्थान रांची ने अपना 12 वां स्थापना दिवस मनाया। ज्ञात हो कि अब तक इस संस्थान के समस्त छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किराये के स्थानों पर किया जा रहा था। अब आई.आई.एम. रांची स्वंय को इस उपलब्धि से स्वतंत्र और उत्साहित महसूस कर रहे है।

सांसद परिमल नाथवानी ने आई. आई. एम. रांची के नये सेमिनार खंड के उद्घाटन समारोह में कहा कि, ''भारत के शीर्ष प्रबंधन संस्थाओं में स्थान पाने वाली भारतीय प्रबंधन संस्थान राँची, के विश्वस्तरीय सेमिनार हॉल का उद्घाटन करना, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे सांसद स्थानीक विस्तार विकास निधि से रू. 13.56 करोड़ की लागत से निर्मित 40,000 वर्ग फुट में फैले हुए इस ओडिटोरियम की क्षमता 650 लोंगो की है। आई. आई. एम. रांची के स्थापना से ही उसका अभ्यासक्रम इस तरह से तैयार किया गया है जिससे प्रबधंन संस्थान में जो पढ़ाया जाता है और वास्तविक रूप से व्यवसाय में जो चाहिए उसके बीच की दूरी को कम किया जा सके। यह सेमिनार हॉल शैक्षणिक विश्व और कॉर्पोरेट को जोड़ने का कार्य करेगा। मै आशा करता हूँ कि यह सेमिनार हॉल लर्निंग सेन्टर के रूप में उभर कर आए जहाँ भारत और समुचे विश्व से शीर्ष कंपनी के सीईओ, व्यावसायिक जगत के निष्णात और मेनेजमेन्ट गुरू आए और यहां के विद्यार्थीओं और प्राध्यापको के साथ वार्तालाप करें और अपना ज्ञान साझा करें।

परिमल नाथवानी के सांसद स्थानीक विस्तार विकास निधि के रू. 13.56 करोड़ की लागत से बन कर आइआइएम रांची कैम्पस को मिला पहला भवन

नया भवन पूर्ण रुप से वातानुकूलित सभागार है। यहां 650 लोगों की क्षमता वाला आधुनिक आई.टी. तकनिकों, ओडियो-विडियो सुविधा से लैस है सभागार

निदेशक आई.आई.एम. रांची ने कहा कि रांची ने कोरोना महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन जैसी चुनौतियों के बाद इस उप्लब्धि को हासिल किया है आज का यह समारोह लक्ष्य को हासिल करने के लिए इच्छा शक्ति के महत्व को साबित करता है। आज उद्घाटन के दिन भी सार्वजनिक सभाएँ, स्वास्थय और सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित हैं, लेकिन फिर भी संस्थान ने उद्घाटन कार्यक्रम को ऑनालईन मोड में आयोजित कर ''जहां चाह वही राह'' को साबित किया है। सांसद परिमल नाथवानी जी ने इस भवन के उद्घाटन में उपस्थित होकर बड़ा सहयोग प्रदान किया है। उन्होनें उम्मीद जताायी है कि यह भवन देश-दुनिया के छात्रों के लिए शिक्षा के मंदिर के रुप में विकसित होगा। नाथवानी जी द्वारा इस भवन के निर्माण में भावनात्मक सर्मथन के साथ साथ आर्थिक सहायात भी प्रदान की गई है। राष्ट्र निर्माण में संस्थान की सहभागिता सुनिश्चित करने में श्री नाथवानी जी के संस्थान के साथ भावनात्मक लगाव एवं मार्गदर्शन की सदैव आवश्यकता होगी।

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष, प्रवीण शंकर पांड्या ने परिमल नाथवानी द्वारा प्रदान किए गए सर्मथन के लिए आभार व्यक्त किया है और अपनी इच्छा व्यक्त की, कि भविष्य में इसी तरह संस्थान से जुड़े रहें एवं कोरोना महामारी के उन्मूलन के उपरांत अपनी सुविधानुसार भौतिक रुप से परिसर का दौरा करे।

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, झारखंड एवं देश के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संगठनों का आह्वान करता है और शिक्षण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण में शिक्षा के इस मंदिर का समर्थन करने के लिए आगे आने के लिए कहता है। आई.आई.एम. रांची, इस संस्थान से उत्तीर्ण होने वाले बेहतर प्रबंधको से विश्वभर में झारखंड और भारत को पहचान दिलाने की प्रतिज्ञा लेता है।

राज्य में हर घर तक बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करें

संवाददाता

रांची : झारखंड में बिजली उत्पादन के लिए कोयला और पानी समेत सभी संसाधन उपलब्ध है, फिर भी अपनी जरूरतों के हिसाब से बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं । हमें अन्य स्त्रोतों से बिजली लेनी पड़ रही है । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाएं । इससे ना सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे बल्कि राजस्व में भी इजाफा होगा । बैठक में विभागीय अधिकारियों ने ऊर्जा विकास, उत्पादन, संचरण, वितरण और सेवा से संबंधित योजनाओं की अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया ।

डीवीसी पर निर्भरता खत्म करनी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भरता को खत्म करना है । इस दिशा में विभाग सभी जरूरी कदम उठाए । उन्होंने कहा कि डीवीसी कमांड एरिया वाले 7 जिलों में बिजली आपूर्ति के लिए महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है ।इससे राजस्व का नुकसान होता है ।मुख्यमंत्री ने कहा कि डीवीसी कमांड एरिया में ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनाने के कार्य मे तेजी लाई जाए । विभाग की ओर से बताया गया कि लातेहार -चतरा के बीच ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनकर तैयार है । इसके चालू होने से एक और जिले में बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भरता खत्म हो जाएगी ।डीवीसी से जहां लगभग पांच रुपये यूनिट बिजली खरीदना पड़ता है, वही इसके चालू होने से लगभग 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी ।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए

- पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन सहित बिजली से संबंधित सभी बुनियादी ढांचों को मजबूत करें
- बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिले, कनेक्शन और बिल वितरण जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान हो
- सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा के गैर परंपरागत स्त्रोतों के विकास पर तेजी से हो काम
- ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे
- बिजली उत्पादन वितरणऔर राजस्व संग्रहण की व्यवस्था दुरुस्त होगी
- बिजली के लिए डीवीसी पर पर निर्भरता खत्म होगी।

रांची रेलवे स्टेशन पर कोविड केअर वेंडिंग मशीन लगा

रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर हिंदुस्तान लीवर की ओर से कोविड केअर वेंडिंग मशीन लगाया गया। इस मशीन के द्वारा यात्री शुल्क देकर दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे फेस क्रीम, फेस वाश, बॉडी लोशन, टूथपेस्ट, साबुन, सैनिटाइज़र, मास्क आदि प्राप्त कर सकते है ।

कोरोनावायरस के इस संक्रमण काल में जब सामाजिक दूरी का पालन करना, साबुन, सैनिटाइज़र, मास्क आदि का प्रयोग अति आवश्यक है, इस स्थिति में राँची रेलवे स्टेशन पर लगी यह वेंडिंग मशीन यात्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी है ।

विप्स, सीएमपीडीआई ने किया कार्यशाला का आयोजन

रांची 18 दिसम्बरः वोमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) फोरम, सीएमपीडीआई के तत्वावधान में संस्थान के कांफ्रेंस हॉल में जेंडर अवेयरनेस एंड जेंडर सेंसिटाइज़ेशन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला के अतिथि वक्ता प्रोफेसर (डॉ0) रमन बल्लभ, प्रतिष्ठित शिक्षाविद् एवं वरिष्ठ रिसोर्स पर्सन, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने विभिन्न उदाहरणों, दृष्टांतों और केस स्टडी के माध्यम से यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में कर्मियों को शिक्षित किया। उन्होंने उन महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया जो हमारे दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में निहित होने चाहिए जो कार्यस्थल पर लैंगिक पूर्वाग्रह और असमानता को कम कर सकते हैं। उन्होंने एक अच्छी तरह से संतुलित कार्य वातावरण बनाने के लिए एक दूसरे के उत्थान और बेहतरी के लिए एक साथ आने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस कार्यशाला में सीएमपीडीआई (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय संस्थान-3 के लगभग 50 पुरूष और महिला अधिकारी एवं कर्मचारीगण भाग लिया। इसके अलावा देश के अन्य भाग में स्थित शेष छह क्षेत्रीय संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से उक्त कार्यशाला में हिस्सा लिया।

सीएमपीडीआई के निदेशक एस0के0 गोमास्ता ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। विप्स, सीएमपीडीआई के समन्वयक एवं महाप्रबंधक श्रीमती सुनीता मेहता ने आगत अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं विप्स के महासचिव एवं विभागाध्यक्ष (सीसी लैब) सुश्री जेबा इमाम ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

15वीं झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैम्पीयनशीप में जेएसएसपीएस कैडेट्स का दबदबा

संवाददाता

खेलगांव, रांची में आयोजित 15वीं झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैम्पीयनशीप 2020 में झारखण्ड स्टेट स्पोर्टस प्रमोशन सोसाईटी (जेएसएसपीएस) (झारखण्ड सरकार एवं सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की सयुंक्त पहल) के युवा कैडेट्स का आज पहले दिन अंडर 14 आयू वर्ग में दबदबा रहा। इतिहास दोहराते हुये जेएसएसपीएस के बच्चों ने आज पहले दिन 6 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक, 1 कास्य पदक विभिन्न खेलों में जीते।

ज्ञात हो कि 18 दिसम्बर से 21 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले 15वीं झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैम्पीयनशीप 2020 में राज्य भर के सभी जिलों से युवा एथलिट विभिन्न वर्ग में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में एक बार फिर जेएसएसपीएस के बच्चों ने अपनी प्रतिभाऔर मेहनत का उदाहरण देते हुये खेल अकादमी का परचम फहराया।

कोरोना काल में इन बच्चों ने घर पर होने के बावजूद अपना प्रशिक्षण निरंतर जारी रखा। अकादमी के विश्वस्तीय प्रशिक्षकों ने ऑनलाईन माध्यम से बच्चों के प्रशिक्षण देते रहे बल्कि इनके खान-पान पर भी पूरा ध्यान अकादमी के प्रबंधन द्वारा दिया जाता रहा। आवश्यकता पड़ने पर कई अवसर पर सीसीएल के क्षेत्रिय प्रबंधन द्वारा बच्चों के घर तक राशन पहुंचाया गया।

पहले दिन जेएसएसपीएस का रिजल्ट इस प्रकार है

बॉल थ्रो अंडर 14 बालक वर्ग

बाबूलाल कुमार पासवान - स्वर्ण पदक

उपेद्र उरांव - रजत पदक

बॉल थ्रो अंडर 14 बालिका वर्ग

अनिशा कुमारी - स्वर्ण पदक

पुतूल बासके - रजत पदक

लांग जम्प अंडर 14 बालक वर्ग

दीपक मुण्डा - स्वर्ण पदक

प्रितेश उरांव - रजत पदक

60 मीटर दौड़ अंडर 14 बालक वर्ग

दीपक टोपो - स्वर्ण पदक

दीपक मुण्डा - रजत पदक

60 मी. दौड़ अंडर 14 बालिका वर्ग

पुतूल बासके - स्वर्ण पदक

रितु कुमारी - रजत पदक

600 मी॰ दौड़ अंडर 14 बालक वर्ग

केशव कुमार - रजत पदक

मोनिश रजा - कास्य पदक

600 मी. दौड़ अंडर 14 बालिका वर्ग

अनिशा कुमारी - स्वर्ण पदक

जेकलिन खेश -रजत पदक

फोटो न्यूज

इंसानी कृत्य को जरा गौर से देखें

करी पत्ते मे छुपा सेहत का खजाना

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

भारतीय रसोई स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी खजाना है।आज हम बात करेंगे करी पत्ते के बारे मे ।ज्यादातर इसे दक्षिण भारत मे इस्तेमाल किया जाता है परन्तु इसकी गुणवत्ता के कारण अब देश विदेश मे इसका प्रयोग होने लगा है।

करी पत्ता का वैज्ञानिक नाम मुराया है,अंग्रेजी मे करी लीफ और संस्कृत मे कृष्ण निंबा कहते है।इसको मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नीम के पत्तो के जैसे दिखते है।करी पत्ता मे कई औषधीय गुण होते है ,जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के साथ-साथ त्वचा और बालो को भी स्वस्थ और चमकदार बनाता है।इसमे आयरन कैल्शियम, विटामिन बी 1,विटामिन बी 2, विटामिन-सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते है। इनमे एंटी डायबिटीक और एंटी-ऑक्सिडेंट पाया जाता है।

करी पत्ता के कुछ फायदे

- डायबिटीज मे फायदेमंद- डायबिटीज के रोगी के लिए करी पत्ते का सेवन करना बेहद फायदेमंद है।ये इंसुलिन लेबल को नियंत्रित करता है और ब्लड शुगर लेबल को कम करता है।सुबह-सुबह खाली पेट 8-10 पत्ते को कच्चा चबाकर खाना लाभदायक होता है।

- हृदय को स्वस्थ रखता है- ये शरीर के हानिकारक कोलेस्ट्रोल लेबल का संतुलन रखता है, जिससे हृदय की बीमारियों से बचाव होता है।
- बालो के लिए वरदान-करी पत्ता बालो के लिए वरदान से कम नही है।इसके इस्तेमाल से बाल स्वास्थ्य, काले और चमकदार होते है।आप इसे पीस कर बालो में लगा सकते है,अपने तेल मे करी पत्ते को उबालकर उसे बालो मे लगा सकते है।अपने खाने मे इसका इस्तेमाल करना आसान और प्रभावी तरीका है।
- लीवर का ख्याल - यह लीवर को सशक्त बनाता है ,बैक्टीरिया तथा वायरल इंफेक्शन से बचाता है,साथ ही फ्री रेडिकल्स, हेपटाइटिस जैसी बीमारियो से बचाता है।
- आँखों को स्वस्थ रखता है- करी पत्ता मे विटामिन ए प्रचुर मात्रा मे होता है ,इसलिए ये आँखों के लिए स्वस्थ रखता है।
- एनीमिया मे सहायक - एनीमिया के इलाज के लिए आयरन की ोली खानी होती है ,और करी पत्ते मे आयरन प्रचुर मात्रा मे है इसीलिए खून की कमी की शिकायत दूर होती है।
- चेहरे पर रौनक के लिए- चेहरे की समस्या जैसे मुहांसे ,रुखापन, दाग-धब्बे होने पर करी पत्ता को सुखा के गुलाबजल या शहद मे मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की समस्या दूर हो जाती है और चेहरे पर निखार आता है।

अब हमेशा याद रखे कि अपने व्यंजनो मे से करी पत्ते को निकाल के बाहर रखने से बेहतर है कि हम उसे चबाकर खाये।

ब्रिटेन में अब नया कोरोनावायरस

एजेंसियां

ब्रिटेन में कोरोनावायरस के नए प्रकार (स्ट्रेन) को लेकर भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है।

ब्रिटेन ने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस के नए प्रकार की वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस वजह से रविवार से वहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी गैर जरूरी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है। इंग्लैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रो. क्रिस विट्टी ने कहा है कि हमने कोरोनावायरस के नए प्रकार के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को जानकारी दे दी है और बताया है कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। संक्रमण के नए प्रसार को काबू में करने के लिए कई सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इनमें क्रिसमस बबल प्रमुख है। यह पांच दिन तक चलता है। पहले इस कार्यक्रम के लिए प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है।

कई यूरोपीय और अरब देशों ने ब्रिटेन से आने-जाने वाली हवाई उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ब्रिटेन से आने वाली हवाई उड़ानों पर पाबंदी की अपील की थी। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार हर स्थिति को लेकर सचेत है और समय पर सही फैसला लिया जाएगा।

अपने उत्पाद को बेचने में सक्षम नहीं होना ही किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा है

लगातार छह साल तक, बागवानी (फल और सब्जियां) उत्पादन अनाज उत्पादन से आगे रहा है। हाल के समय में, बागवानी का उदय, कृषि विकास का एक कम स्वीकार्य पहलू रहा है। विशेषकर 2004-14 के उच्च विकास चरण के दौरान। हालांकि यह सिर्फ खेती के 20 प्रतिशत हिस्से को ही कवर करता है, लेकिन यह कृषि जीडीपी में एक तिहाई से भी ज्यादा का योगदान देता है। पशुधन के साथ, कृषि के इन दो उपक्षेत्रों में वृद्धि जारी रही है और ये अधिकतम रोजगार भी दे रहे हैं। देश में फलों और सब्जियों का उत्पादन, खाद्यान्न से आगे निकल गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक बयान में कहा गया है कि वर्ष 2016-17 (पूर्वानुमान) के दौरान 300.6 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है।

बागवानी किसानों की सबसे बड़ी चुनौती बिक्री और फसल होने के बाद में होने वाली हानि (बर्बादी) है। इससे यह किसानों के लिए कम आकर्षक सेक्टर बन जाता है। हालांकि, सरकार ये बात गर्व के साथ कहती है कि भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि फसल पैदा होने के बाद होने वाली बर्बादी की वजह से फल और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता काफी कम है। फल और सब्जियों की बर्बादी कुल उत्पादन का लगभग 25 से 30 प्रतिशत होता है।

फल और सब्जियों की ये बर्बादी शीत गृह की संख्या में कमी, कमजोर अवसंरचना, अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज क्षमता, खेतों के निकट कोल्ड स्टोरेज का न होना और कमजोर परिवहन साधन की वजह से होती है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए बनी कमेटी के मुताबिक, किसानों को 34% फल, 44.6%,सब्जियां और 40 फीसदी फल और सब्जी के लिए मौद्रिक लाभ नहीं मिल पाता है। यानी, इतनी मात्रा में फल और सब्जियां किसान बेच नहीं पाते या बर्बाद हो जाती है।इसका मतलब है कि हर साल, किसानों को अपने उत्पाद नहीं बेच पाने के कारण 63,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता है।

मधुमक्खियों की प्रजातियों का बना पहला नक्शा

एजेंसियां

शोधकर्ताओं ने लगभग 60 लाख सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर पहचानी गई मधुमक्खी की प्रजातियों की पूर्ण वैश्विक चेकलिस्ट को मिलाकर मधुमक्खी विविधता का एक नक्शा बनाया है।

मधुमक्खी की 20 हजार से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन ये दुनिया भर में कैसे फैली इसके बारे में सटीक आंकड़े मिलना मुश्किल हैं। हालांकि अब शोधकर्ताओं ने लगभग 60 लाख सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर पहचानी गई मधुमक्खी की प्रजातियों की पूर्ण वैश्विक चेकलिस्ट को मिलाकर मधुमक्खी विविधता का एक नक्शा बनाया है। आज दुनिया भर में अलग-अलत प्रजातियां दिखाई देती हैं। टीम ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी, उष्णकटिबंधीय और शुष्क वातावरण की तुलना में मधुमक्खियों की अधिक प्रजातियां हैं।

सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर जॉन असचर कहते हैं कि पक्षियों और स्तनधारियों की तुलना में मधुमक्खियों की अधिक प्रजातियां हैं। अमेरिका में अभी तक मधुमक्खियों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई गई हैं, लेकिन अफ्रीकी

महाद्वीप और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्र भी हैं जिनमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अनदेखे विविधता का स्तर अधिक है।

नक्शा बनाने के लिए सहकर्मियों ने डॉ असचर द्वारा संकलित 20 हजार से अधिक प्रजातियों की एक विशाल चेकलिस्ट के साथ आंकड़ों की तुलना की जो कि जैव विविधता पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। पहले के कई डेटासेटों को क्रॉस-रेफ़र करने के परिणामस्वरूप मधुमक्खियों की कई प्रजातियों को अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बाटा गया है। यह मधुमक्खी आबादी के वितरण और संभावित गिरावट का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। यह रिपोर्ट जर्नल करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। इनमें से कुछ पैटर्न चार्ल्स मिस्नर जैसे पिछले शोधकर्ताओं द्वारा डाले गए थे, जोकि गलत, अपूर्ण, थे जिसके कारण प्रजातियों के बारे में सही आकलन करना मुश्किल था। आंकड़ों का सही तरीके से मिलान करना शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा थी। हालांकि मधुमक्खी विविधता क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, शोध टीम को उम्मीद है कि उनके काम से दुनिया भर में परागणकर्ताओं के रूप में मधुमक्खियों के संरक्षण में मदद मिलेगी।

एकेडमी ऑफ़ साइंसेज में संरक्षण जीव विज्ञान के एक एसोसिएट प्रोफेसर ऐलिस ह्यूजेस ने कहा मुझे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में मधुमक्खी की विविधता के बारे में वैश्विक आंकड़ों को कितनी बुरी तरह से रखा गया था। आंकड़े बहुत ही कम या बहुत कम देशों पर केंद्रित थे। ह्यूजेस कहते हैं कि दुनिया भर में कई फसलें, विशेषकर विकासशील देशों में देशी मधुमक्खी की प्रजातियों पर निर्भर रहती हैं। उनके बारे में पर्याप्त आंकड़े नहीं है। यदि भविष्य में हमें जैव विविधता और इन प्रजातियों से मिलने वाली सेवाओं को बरकरार रखना है तो इसका सही आधार प्रदान करना और सही से विश्लेषण करना आवश्यक है।

ओक प्रजातियों पर मंडरा रहा है विलुप्ति का वैश्विक खतरा

दुनिया भर में ओक की 31 फीसदी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन, कीटों, कृषि, जंगलों के विनाश और शहरीकरण को जिम्मेवार माना जा रहा है द मॉर्टन अर्बोरटम और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के ग्लोबल ट्री स्पेशलिस्ट ग्रुप द्वारा जारी नई रिपोर्ट द रेड लिस्ट ऑफ ओक्स 2020 से पता चला है कि दुनियाभर में ओक की करीब 31 फीसदी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट में पहली बार दुनिया की 430 ओक प्रजातियों के वितरण, पेड़ों की संख्या और उसपर मंडरा रहे खतरों के बारे में जानकारी दी गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रिपोर्ट की मदद से ओक के वृक्षों के संरक्षण में मदद मिलेगी।

शोधकर्ताओं के अनुसार एक तरफ जहां 31 फीसदी ओक प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा है वहीं साथ ही करीब 41 फीसदी (217) को संरक्षण की जरुरत है। यदि इस प्रजाति पर मंडरा रहे विलुप्त होने के खतरे की बात करें तो वह स्तनधारी जीवों (26 फीसदी) और पक्षियों (14 फीसदी) से भी कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा चीन में मौजूद ओक प्रजातियों पर खतरा है

वहां इसकी करीब 36 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। इसके बाद मेक्सिको (32 प्रजातियां), वियतनाम (20) और संयुक्त राज्य अमेरिका (16) का नंबर आता है। भारत में भी ओक की करीब 21 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 संकटग्रस्त हैं। किस कारण विलुप्त हो रहे हैं यह पेड़

वैज्ञानिकों द्वारा ओक पर मंडरा रहे खतरों के विश्लेषण से पता चला है कि अमेरिका में इसके विलुप्त होने के लिए जलवायु परिवर्तन, आक्रामक कीट और रोग मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में कृषि, शहरीकरण और जंगलों का विनाश मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। भारत में कृषि के चलते यह पेड़ खतरे में है।बॉटनिक गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल (बीजीसीआई) के महासचिव पॉल स्मिथ के अनुसार अकेले ब्रिटेन में पक्षी, काई, कवक, कीड़े, लाइकेन और स्तनधारी जीवों की करीब 2300 प्रजातियां भोजन और आश्रय के लिए देशी ओक पर निर्भर हैं। यही बात ओक की अन्य प्रजातियों पर भी लागु होती है। ऐसे में यदि इसकी एक भी प्रजाति विलुप्त होती है तो उसका खामियाजा सैकड़ों अन्य प्रजातियों को भी उठाना पड़ेगा।

ओक को बांज, बलूत या शाहबलूत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लगभग 400 से भी ज्यादा ज्ञात किस्में हैं, जिनमें कुछ की लक-ड़ियां बड़ी मजबूत और रेशे सघन होते हैं। यही वजह है कि इसका उपयोग फर्नीचर और निर्माण में भी होता है। इस पेड़ की पहचान इसके पत्तों और फलों से होती है। इसके पत्ते खांचेदार और फल सामान्यतः गोल और ऊपर की ओर नुकीले होते हैं। आमतौर पर यह पेड़ पूर्व में मलेशिया से हिमालय और काकेशस होते हुए, सिसिली से लेकर उत्तर के ध्रुवीय क्षेत्र के साथ-साथ उत्तरी अमेरिका और भारत में भी पाया जाता है।

ललित मौर्य

मौसम विभाग : इस वर्ष 12 दिन पहले ही मानसून ने दी थी दस्तक

एजेंसियां

इस वर्ष 26 जून तक मानसून देश के सभी हिस्सों में पहुंच चुका था, जोकि इसकी सामान्य तिथि (8 जुलाई) से 12 दिन पहले था

मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2020 के सीजन की अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके अनुसार इस बार देश में मानसून ने सामान्य से 12 दिन पहले ही दस्तक दे दी थी गौरतलब है कि इस वर्ष 26 जून तक मानसून देश के सभी हिस्सों में पहुंच चुका था, जोकि इसकी सामान्य तिथि (8 जुलाई) से 12 दिन पहले था।

रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2020 (जून-सितंबर) के दौरान मौसमी बारिश की लंबी अवधि का औसत (एलपीए) 109 फीसदी थो यह 1994 के 112 फीसदी एलपीए और 2019 के 110 फीसदी एलपीए के बाद तीसरा सबसे अधिक औसत था। यह रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने जारी की है

इस वर्ष उत्तर पश्चिमी भारत में मौसमी बारिश और उनसे संबंधित एलपीए क्रमशः 84 फीसदी रिकॉर्ड किया गयो जबकि मध्य भारत में 115 फीसदी, दक्षिण प्रायद्वीप में 130 फीसदीऔर पूर्वोत्तर भारत में 106 फीसदी दर्ज किया गयो वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून 28 अक्टूबर 2020 को पूरे देश से वापस लौट गया था।

इस मानसून क्या कुछ रहा विशेष

रिपोर्ट के मुताबिक 36 मौसम उपखंडों में से, 2 उपखंडों में (जोकि देश के कुल क्षेत्रफल का 5 फीसदी हैं) बहुत भारी बारिश दर्ज की गईं वहीं 13 उपखंडों में (देश के कुल क्षेत्रफल का 35 फीसदी) अधिक बारिश, 16 उपखंडों में (देश के कुल क्षेत्रफल का 45 फीसदी) सामान्य मौसमी बारिश रिकॉर्ड की गई जबकि बाकी 5 उपखंडों में (जोकि देश के कुल क्षेत्रफल का 15 फीसदी हैं) मानसून के दौरान कम बारिश देखी गई।

इस वर्ष जहां देश में मासिक बारिश एलपीए का योगदान जून में एलपीए 118 फीसदी, जुलाई में 90 फीसदी, अगस्त में 127 फीसदी और सितंबर में एलपीए 104 फीसदी दर्ज किया गया था। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तिथि से 5 दिन पहले, 17 मई 2020 को दक्षिण अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह पहुंचा थो लेकिन बाद में इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। अपने सामान्य समय एक जून को इसने केरल में दस्तक दी थी, जबकि 26 जून 2020 को यह पूरे देश पहुंच चुका था। यदि इसके लौटने की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के पश्चिमी भागों से मानसून 28 सितंबर 2020 को वापस लौटना शुरू हो गया था, जो अपने सामान्य (17 सितंबर 2020) से 11 दिनों की देरी से लौटा थो इस बार देश में मानसून सीजन के दौरान 1 से 4 जून के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान 'निसर्ग' ने दस्तक दी थी

केरल में मानसून की शुरुआत का जो पूर्वानुमान लगाया गया था वो सही साबित हुआ। यह 2005 में केरल से शुरु किए गए पूर्वानुमान के बाद से लगातार पंद्रहवां सही पूर्वानुमान है। हालांकि 2015 में जो पूर्वानुमान लगाया गया था वो गलत साबित हुआ थो केरल में मानसून के शुरुआत की पूर्वानुमान तिथि 5 जून थी, जिसमें 4 दिनों के अंतर था। इस वर्ष केरल में मॉनसून की शुरुआत की सही तारीख 1 जून थी।

मानसून सीजन के लिए पूरे देश में बारिश का पुर्वानुमान तीन व्यापक एकरूपता वाले भौगोलिक क्षेत्रों (मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीप) के लिए किया गया था। इस वर्ष का मॉनसून लॉकडाउन और कम प्रदूषण से प्रभावित था।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।